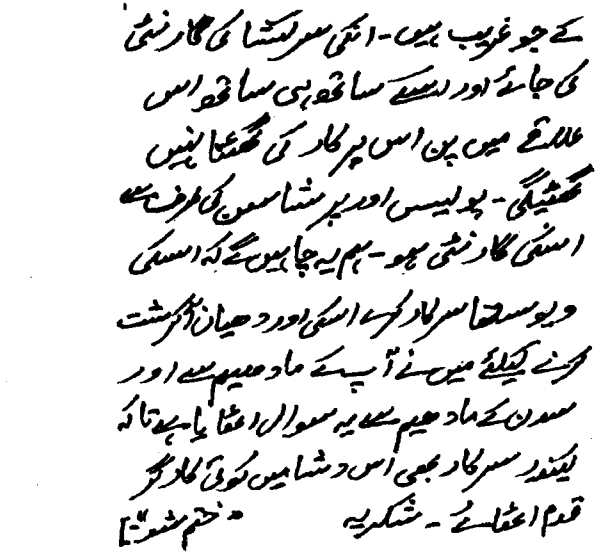

RE: SALE OF SUGAR MILLS IN UTTAR PRADESH

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): धन्यवाद उपसभापति महोदया। कल उत्तर प्रदेश के बजट की चर्चा करते हुए हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समधयान दिलाया था। परसों मैं देवरिया जिला में गई थी और वहां गन्ना किसानों का एक डेलीगेशन मुझसे आकर मिला और अपनी समस्याओं के बारे में उन्होंने मुझे बताया।

माननीया, किसान ऋण लेकर खेती करते हैं लेकिन न तो उन्हें समय पर खाद मिलती है, न कीटनाशक दवाइयां मिलती हैं और गन्ना जब खेत में खड़ा हो जाता है तो अंदाज़ लगाया जा सकता है कि उनकी क्या हालत होगी। उधर गवर्नमेंट द्वारा 14 सहकारी मिलों को बेचने के बाद से स्थिति और भी खराब हो गई है और जो निजी मिल-मालिक हैं, वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। राज्यपाल ने गन्ने की कीमत 70 से 72 रुपए क्विंटल और 74 रुपए क्विंटल कर दी। इसके खिलाफ चीनी मिल-मालिकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और उन्हें स्टे भी मिल गया। इससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। अब जब गन्ना-किसान मिलों में अपना गन्ना बेचने जाते हैं तो मिल-मालिक उनके साथ बारगेनिंग करते हैं कि 40, 42 अथवा 62 रुपए तक ही वे लेंगे अन्यथा उन्हें जो पुरजी दी जाती है उस पर, रेट फिक्स नहीं है इसलिए पेंडिंग रेट की मोहर लगा दी जाती है और उन्हें बहुत ही मजबूरी का सामना करना पड़ता है। ऐसी हालत में आपके सामने यह मांग रखना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी उनकी बकाया रकम का भुगतान किया जाए। प्रधान मंत्री ने भी कुछ दिन पहले आश्वासन दिया था कि जो बकाया है, उसका भुगतान किया जाएगा किन्तु अब तक सरकारी मिलें भी 50 परसैंट से अधिक भुगतान नहीं कर पाई हैं। ऐसे हालात में मैं आपके माध्यम से तीन बातें रखना चाहूंगी कि:—

1. खेत में खड़ी फसल के आधार पर सट्टा नीति तय की जाए।

2. तुरन्त पिछले और वर्तमान बकायों का निबटारा किया जाए, सरकार द्वारा घोषित मूल्य के आधार पर। और

3. तौल में जो धांधली होती है, उसके लिए प्रत्येक तौल कांटे पर जिला गन्नाधिकारी द्वारा एक सर्वेक्षक नियुक्त किया जाए, जिससे यह धांधली न हो। धन्यवाद।

RE: RELEASE OF 39 INDIAN CHILDREN DETAINED IN PAKISTANI JAILS

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, I would like to raise the plight of 40 Indian children who are languishing in the Pakistani jails. I gave this notice on Monday, but I am told that the attention of the House was already focussed on this issue. Mr. Gujral is aware of this. His Ministry is involved in this. Mr. Gujral should intervene in the matter and see that these children are released from the Pakistani jails.

Madam, this matter was raised by the BBC. The Amnesty International has taken up this matter. But there is no attempt by the Government of India to see that these children are brought back to India. These children were taken away from the Saurashtra-Kutch region by fishing boats which were on long voyages.

The hon. Supreme Court had recently delivered a landmark judgement on child labour. I want to know from the Minister of External Affairs the steps being taken by him to bring back these children to India and to rehabilitate them. At the

same time, I want also to know the steps the Central Government has taken to direct the State Government to stop child labour.

THE DEPUTY CHAIRMAN: How are they in Pakistan?

SHRI JOHN F. FERNANDES: They were taken away by the fishing boats. The Pakistani marines had arrested them. They were put in the Pakistani jails and they have been in the Pakistani jails for the last three years. When they were taken away, they were about 8 years. Now they are 11 years old, very young boys. The Central Government is doing nothing about it. They are just languishing in Karachi jails. Out of the 40 boys, one boy died. There are now 39 boys who are languishing there, in some charitable organisations. But the Foreign Minister knows about it. But no attempt has been made by the Government to bring them back to India. I want to have the reaction of the Minister of External Affairs. Mr. Gujral knows about it. I would like him to see that an authority is constituted by the Government of India to implement the direction of the Supreme Court, to implement the latest decision of the Supreme Court banning child labour.

Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You see, this is a very serious matter. The children were smuggled or they were taken away by force. They had been arrested by the Pakistani authorities. I think our Government should take...

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, they were languishing in prison and nothing was done by the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. We should do something. Our defence Minister is here representing the Government.

मुलायम सिंह जी, हिंदुस्तान के 39 बच्चे पाकिस्तान की जेलों में हैं। मछुआरे लोग उनको अपनी बोट्स में यहां से ले गए थे, वे पकड़े गए समुंदर में और वे जेलों में बंद है।

SHRI JOHN F. FERNANDES: No, Madam. They have been got released by Amnesty International and they are now with the NGOs. They have to be brought back.

उपसभापति: ऐमनैस्टी इंटरनेशनल ने उनको छोड़ दिया है और अब वे एन०जी० ओज० के पास हैं। उनको वापस हिन्दुस्तान आना चाहिए। इसके लिए सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए।

SHRI RAGHAVJI (Madhya Pradesh): Madam, I think the whole House is...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the whole House and I think the whole country would like the children to be back.

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): उपसभापति महोदया, कल समाचारपत्रों में जो आया था और हमें और भी जो जानकारी मिली थी, उसके बाद हमने कल वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की थी और मैं कल तक विदेश मंत्री जी से बात करके उन्हें छुड़ाने का प्रयास करूंगा।

श्री एन०के०पी० साल्वे (महाराष्ट्र): महोदया, रक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है, हम इनके बहुत ऐहसानमंद हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन यह मामला ऐक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के दायरे में आता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में उन्हें डॉयरेक्शन दें।

उपसभापति: ऐक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इस वक्त यहां नहीं हैं, इसीलिए मैंने रक्षा मंत्री जी से कहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदया, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं कल तक विदेश मंत्री जी से बात करके उन्हें छुड़ाने की कोशिश करूंगा।

SHRI N.K.P. SALVE: Madam, ...

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE (Maharashtra): He said that he was taking the responsibility. He said that he would talk to the Minister of External Affairs.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is a meeting of the Foreign Ministers of SAARC countries today or tomorrow. I

think the Foreign Minister can take up this issue there.

Today we have a lunch hosted by the Chairman for the new Members. So, I will adjourn the House three minutes before for the new Members to reach there. Some of them are here and some of them have already gone.

I also want to make an announcement that all the Zero Hour submissions and Special Mentions which are pending and for which permission has been granted, will be taken up after the Short Duration Discussion. We want to clear all the business that is pending before we adjourn the House *sine die* in two days' time. All the pending matters which the Members feel...

AN HON. MEMBER: What about special mentions?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I said that Zero Hour submissions and Special Mentions will be taken up after the Short Duration Discussion so that whatever matters you want to raise about your constituencies are finished before we adjourn the House *sine die* in two days. You should not go back home saying that you wished to raise it.

The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at fifty-eight minutes past twelve of the clock.

2.00 P.M.

The House re-assembled after lunch at five minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri MD. Salim)** *in the Chair.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We will take up Short Duration Discussion.

SHORT DURATION DISCUSSION

The Steep Rise in Prices of Essential Commodities

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली) उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब बनी थी लगभग छह माह पूर्व तो उस समय इसे जनता का समर्थन तो था नहीं और एक तिकड़म और भानुमती के पिटारे की तरह तेरह दिशाओं में दौड़ने वाले घोड़ों से खींचे गए रथ की तरह से तेरह दलों की यह सरकार बनी थी परंतु इसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वे हम्बल फार्मर हैं, एक विनीत किसान हैं। कांग्रेस पार्टी और जनता दल का समर्थन इस सरकार को प्राप्त है और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है। तो लोगों को आशा थी कि कम से कम गरीबों और किसानों का यह सरकार शायद समर्थन करेगी, उनको कुछ राहत पहुंचाएगी। परंतु उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार के छह महीने के काल में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जमाखोरों को, मुनाफाखोरों को, दलालों को, बिचौलियों को, पूंजीपतियों को और बड़े-बड़े धन्ना सेठ किसानों को और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है गरीबों को, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले, स्लम में रहने वाले लोगों को। सबसे ज्यादा खून चूसा गया है आम आदमी का, किसान का और उसको यह नुकसान पहुंचाया गया। आटे और गेहूं का जो पिछले दिनों स्कैंडल हुआ, जो महंगाई हुई, यह आजाद हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़ा घोटाला है। इससे पहले आटे और गेहूं की कीमतों में इतना बड़ा घोटाला, इतना भ्रष्टाचार और इतना निकम्मापन किसी सरकार ने नहीं दिखाया। इन पिछले दो महीनों में ही गरीब आदमी की जेब से करीब पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि निकल गई और बड़े-बड़े जमाखोरों के पास पहुंच गई। मैं इस बात का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि रुपए की कीमत जैसा कि अखबार में पिछले दिनों आया था, 5.9 पैसे रह गई है क्योंकि यह सरकार उसकी पूरी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकती। यह तो 1962 के बाद, बेस ईयर 1962 को मानकर, यह 5.9 पैसे रह गई। यह सरकार तो छह महीने की है लेकिन इस समय जो होलसेल प्राइस इन्डेक्स है वह 6.8 परसेंट है और जब यह सरकार बनी थी तब यह 4.77 परसेंट था। तो 4.77 परसेंट छह महीने के अंदर होलसेल प्राइस इन्डेक्स बढ़ा है परंतु होलसेल इन्डेक्स हिंदुस्तान के आम आदमी की कीमतों का कोई आईना नहीं है। यह उसका कोई शीशा नहीं है। वह है कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स और कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स, अक्टूबर के महीने का जो